tor obtaining the previous sanction of the President and the administrative approval of the Government of India, before its introduction in the State Legislature. The Bill is receiving the attention of the Government of India.

Cultivable land in the Melghat region

1880. DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) what is the exact size of gross cultivable land in the Melghat region of Amravati District of Maharashtra;

(b) what is the extent to which agriculture is developed on this land in the tribal area;

(c) whether Government are aware that more than 4000 children have died due to malnutrition and disease during the last three years in this area; and

(d) what special plans have this department got for developing agriculture efficiently in this area?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (DR. S. VENUGOPALACHARI): (a) The gross cultivable land in Melghat region is 76958 hectare.

(b) The tribals have traditionally been growing kodo, kutki, local jowar and local paddy varieties. By introducing modern technology of agriculture, tribals are growing improved varieties of soyabean, improved and hybrid jowar varieties, improved paddy varieties and other crops like cotton, gram, wheat etc. The tribals have also switched over to horticulture crops through EGS and the plantations in about 562 hectare had been undertaken for crops such as mango, orange, sweet lime and dry fruit plantations like Ber, Sitaphal etc. The tribals are adopting the modern technology in agriculture such as use of improved seeds, fertilisers, improved agricultural implements, drip/sprinklers, etc. to increase the level of per hectare production.

(c) During the rainy season in the last three years i.e. 1994-95, 1995-96 and 1996-97, a total of 1289 children below six years have died due to various causes such as fever, pneumonia, diarrhoea and dysentery, pre-maturity, tuberculosis, measles and other diseases.

(d) For all round development of tribals, the schemes such as distribution of hybrid and improved seeds, fertilisers, improved agricultural implements, conduct of demonstrations on different crops, arranging training classes for cultivators on modern technology and plantation of horticultural crops under EGS are being implemented to boost the production. Zilla Parishad also sanctioned Cess Fund Schemes for Welfare of tribals in this area.

In Melghat, bamboo, castor, coffee and mushroom cultivation has been undertaken to increase the economic status of tribals. Further, the Special Tribal Sub Plan Programme is also being implemented.

झींगा मछली उद्योग के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को प्रभावहीन करने के लिए विधेयक

1881. श्री रामगोपाल यादवः
श्री ईश दत्त यादवः

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने झींगा मछली उद्योग के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को प्रभावहीन करने के लिए संसद के वर्तमान सत्र में कोई विधेयक लाने का निर्णय लिया है या कोई विधेयक ला रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) सरकार के इस कदम/निर्णय का समाज के बुद्धिजीवियों, पर्यावरण के प्रति जागरूक लोगों तथा झींगा मछली उत्पादन से प्रभावित तटीय क्षेत्रों पर रहने वाले लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० एस० वेणुगोपालाचारी): (क) और (ख) जलकृषि प्राधिकरण विधेयक 1997 राज्य सभा में 20.3.1997 को प्रस्तुत किया गया और इसे पारित किया गया। इस विधेयक में जलकृषि से संबंधित कार्यकलापों का विनियमन करने के लिए तथा उससे संबंधित मामलों से निपटने अथवा उससे प्रासंगिक मामलों के लिए एक जलकृषि प्राधिकरण की स्थापना करने का प्रावधान है।

(ग) इस विधेयक के मुख्य उद्देश्यों में से एक जलकृषि फार्मिंग का भविष्य में इस तरह का विकास करना है जो पर्यावरण को सुरक्षित रखने की जरूरत के अनुरूप हो। यह भी प्रस्ताव है कि एक जलकृषि प्राधिकरण की स्थापना की जाए ताकि विद्यमान जलकृषि फार्मों के मामलों की समीक्षा की जा सके और सुनिश्चित किया जा सके ताकि केवल उन्हीं को जलकृषि फार्मिंग करने की अनुमति प्रदान की जाएगी जो पारिस्थितिकी के अनुकूल यह कार्य कर रहे हैं।

उत्तरी भारत में बाढ़ से जान-माल और फसलों की क्षति

1882. श्री ईश दत्त यादव:
श्री रामगोपाल यादव:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बाढ़ से अब तक उत्तर भारत में कौन-कौन से राज्य अधिक प्रभावित हुए हैं तथा किस राज्य में जान-माल एवं फसल की सबसे अधिक बरबादी हुई है;

(ख) उत्तर प्रदेश में अब तक बाढ़ से कितने लोग मरे हैं; कितने बेघर हुए हैं और कितनी फसलों का नुकसान हुआ है; और

(ग) उत्तर प्रदेश में बाढ़ से प्रभावित लोगों और मृतकों के परिजनों/आश्रितों को राहत प्रदान करने के लिए सरकार ने अपने स्तर पर अब तक क्या कार्यवाही की है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० एस० वेणुगोपालाचारी): (क) राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, वर्तमान दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान उत्तरी भारत में हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ भाग भारी वर्षा, बाढ़ों और भू-स्खलन से भिन्न-भिन्न मात्रा में प्रभावित हुए।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, वर्तमान मानसून के दौरान भारी वर्षा, बाढ़ और भू-स्खलन से अब तक 41 लोगों की जानें गई हैं और 959 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं तथा 14000 हैक्टेयर क्षेत्र में फसलों को नुकसान पहुंचा है।

(ग) भारत सरकार ने आपदा राहत निधि के केन्द्रीय हिस्से की 49.51 करोड़ रुपए की दो किश्तें निर्मुक्त की हैं ताकि प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास उपाय किए जा सकें।

NHRC warning on starvation ignored

1883. SHRI SHUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE:
SHRIMATI VEENA VERMA:
SHRI KRISHAN KUMAR BIRLA:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item captioned, "NHRC warnings on starvation ignored" which appeared in the 'Tribune' of June, 1997;

(b) if so, whether the NHRC team which visited the drought hit areas of Kalahandi, Bolangir, Auapada districts and others in Orissa last year, had recommended immediate emergency steps to help the worst draught-hit areas out of the jaws of starvation and death;

(c) whether people in large numbers have been forced to migrate from these areas in the absence of any drought relief measures; and

(d) Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (DR. S. VENUGOPALACHARI): (a) Yes, Sir.

(b) A Team of officers of the NHRC had visited some of the drought affected areas of Orissa in December 1996 to investigate the reported starvation deaths. The Commission has not yet finalised its report.